VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2069)

Name of Candidate	Arun Rambha		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1206849
Center	New Delhi	Date	4.09.2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks. 12.5X20=250

1. Discuss the various forms of regionalism that have emerged in India since independence.

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उभरे क्षेत्रवाद के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए।

क्षेत्रवाद से आशय किसी समूह विशेष द्वारा अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक हितो की रक्षा करने के क्रम में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करना अथवा उसका प्रयास करने से है।

स्वतंत्रता की प्राप्ति पश्चात् भारत मे क्षेत्रवाद के रूप

(अ) भाषागत क्षेत्रवाद → भारत विविध भाषाओ (500+ भाषाएँ एवं 1632 बोलिया) वाला देश है।

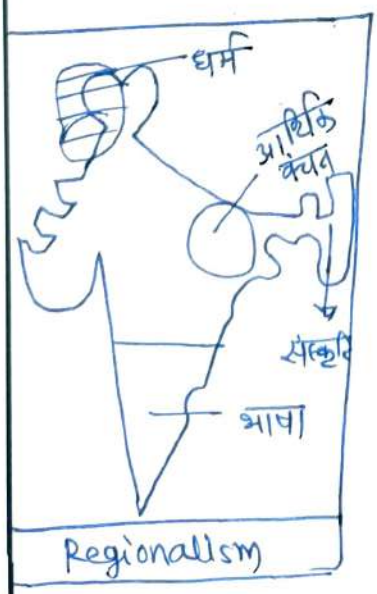

→ आजादी पश्चात द्रविड़ राज्यो द्वारा सर्वप्रथम भाषायी विवाद (आंध्रप्रदेश) मे शुरुआत

→ फजल अली की अध्यक्षता में भाषायी आधार पर राज्यो का गठन

- आंध्रप्रदेश (तेलगू)
- तमिलनाडु (तमिल)
- केरल (मलयालम)
- कर्नाटक (कन्नड़)
- उत्तर में 09 हिन्दी भाषी राज्य एवं अन्य

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ब) धर्म के आधार पर → धार्मिक उन्माद एवं साम्प्रदायिकता के नाम पर

जैसे → खालिस्तान की मांग इत्यादि।

(स) आर्थिक क्षेत्रवाद → ① आर्थिक असंतुलन
↓
क्षेत्रीय असमानताओ के कारण क्षेत्रवाद की भावना का प्रसार
जैसे → बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मांग

② आर्थिक दोहन

→ अत्यधिक आर्थिक दोहन की स्थिति भी क्षेत्रवाद को उत्पन्न करती है।
जैसे : छत्तीसगढ़ खनिज का म.प्र. सरकार के अत्यधिक दोहन स्वरूप छत्तीसगढ़ का 2001 में अलग राज्य बनना

(द) सांस्कृतिक एवं नृजातीय क्षेत्रीयता

→ पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक अस्मिता तथा नृजातीय गौरवता के परिणामत: क्षेत्रवाद
जैसे : कूकीलैण्ड, बोडोलैण्ड की मांग

→ आदिवासी संस्कृति की रक्षा हेतु
↓ उत्तराखण्ड ↓ छत्तीसगढ़ ↓ झारखण्ड
का उदय होना।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्टतः भारतीय समाज की विविधता क्षेत्रवाद की स्थिति को उत्पन्न करती है। परन्तु 'भारतीय संविधान' तथा 'संघीय ढाँचें' एवं ~~एकता~~ 'अनेकता में एकता' का भारतीय सिद्धान्त इसे एकीकृत एवं अखण्ड बनाए हुए है।

2. Although globalisation has created new opportunities for women in India, it has created some issues as well. Discuss.

हालांकि वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित किए हैं, लेकिन इसने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न की हैं। विवेचना कीजिए।

उत्तर ⇒ वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न लोगो का समूह मिलकर 'ग्लोबल सोसायटी' की स्थापना करता है। तथा यह ग्लोबल सोसायटी मिलकर सामाजिक- सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी एवं राजनैतिक मूल्यों एवं विचारों का आदान-प्रदान करती है।

वैश्वीकरण ⇒ दो धारी तलवार → भारतीय समाज पर प्रभाव

- संरचनात्मक बदलाव
  - संख्याओं पर
    - जाति
    - विवाह
  - वर्गों पर
    - महिला
- सांस्कृतिक बदलाव
  - समजातीयता
  - भूमण्डलीकरण
  - इत्यादि

वैश्वीकरण से महिलाओं के लिए नवीन अवसर

→ आर्थिक अवसरों में वृद्धि → सूचना प्रौद्योगिकी में महिलाओं के लिए नवीन नौकरियों का सृजन
  → 'पिंक कालर जॉब' से परे नवीन जॉब भी
  जैसे:- महिलाओं का अभियन्ता (इंजीनीयर) अंतरिक्ष वैज्ञानिक इत्यादि बनना

→ संगठित क्षेत्रों में अवसर → लगभग 20% महिलाए बहुराष्ट्रीय कम्पनी में CEO है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ सोशल इन्फ्लुंजर, सोशल मीडिया पर विडियो, यूट्यूब, फेसबुक, वाट्सअप इत्यादि का इष्टतम उपयोग।

जैसे :- कई गृहणियाँ 'Youtube' के माध्यम से 'खाना पकाने की रेसिपिया' सिखाती है

- Whatsapp के द्वारा कुटीर उद्योग उत्पादो का व्यापार करना इत्यादि

⑤ राजनीतिक सशक्तिकरण → सक्रियतावादी (1975) आंदोलन के पश्चात् राजनीतिक रूप से महिलाएं सशक्त, प्रतिनिधित्व में आरक्षण की मांग, 'ग्लास सिलिंग' जो बहुत हद तक तोड़।

Eg → भारत > पंचायतो में > महिलाओ > $\frac{1}{3}$ rd आरक्षण

⑥ ग्लोबल वूमेन → UN WOMEN जैसे संगठन तथा ~~MeToo~~ #Metoo जैसे अभियान से ग्लोबल वूमेन बनी।

⑦ अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रो (कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र) में भागीदारी बढ़ी।

⑧ स्वास्थ्य, शिक्षा, पितृसत्तात्मकता पर वैश्विक जंग छिड़ी है।

वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएँ

- नवीन तकनीकियों का विकास → कन्या भ्रुण हत्या की समस्या
- रात्रि में कार्य (IT सेक्टर में) → कार्यस्थल पर यौन अपराध में वृद्धि
- पुरुषो की तुलना में न्यूनतम वेतन (0.7 (महिला) : 1 पुरुष) (ILO)

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ महिला तस्करी, किडनेपिंग की समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी (NCRB की रिपोर्ट)

→ अत्यधिक प्रतियोगी वातावरण में महिलाओं की काबिल की अनदेखी उन्हें 'सकारात्मक भेदभाव' (अन्य मानदण्ड अनुरूप) प्रदान नहीं

→ वैश्वीकरण से शहरीकरण /औद्योगीकिकरण बढ़ा।

∘) निम्नवर्गीय शहरी महिलाओं की स्थिति अत्यधिक गंभीर

∘) अपने बच्चे की देख रेख प्रभावित

महिलाओं के पति का शहरों में आना
↓
∘) महिलाओं पर कार्य का दोहरा प्रभाव

∘) कृषि का महिलाकरण

वस्तुत: 'भूमण्डलीकरण' एक दो धारी तलवार है जहाँ यह एक ओर नवीन अवसर प्रदान करती है वही दूसरी ओर समस्याओं को भी जन्म देती है। इसका 'सामाजिक प्रभाव आकलन' कर स्थिति सुधारी जा सकती है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Explain the concept of Social Impact Assessment and state its significance.
सामाजिक प्रभाव आकलन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके महत्व को बताइए।

सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का आशय है सरकार द्वारा नीति निर्माण, योजना क्रियान्वयन करते समय सामाजिक पूँजी को होने वाली हानि की गणना करने से है।

सामाजिक प्रभाव आकलन का महत्व

- सामाजिक पूँजी की बचाव सुनिश्चित
- सामाजिक विविधता को ठेस पहुँचाए बिना योजना क्रियान्वयन
- भारत के लिंग, जाति, धर्म, भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे से बचे रहना
- जातिय संघर्ष, साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद जैसे सम्भावित खतरों से बचाव
- मानव विकास सूचकांक में वृद्धि हेतु
- समाज के कमजोर वर्गों को ध्यान कर समावेशी विकास नीति

arunranjbhia1270@gmail.com

Don't write anything in the margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

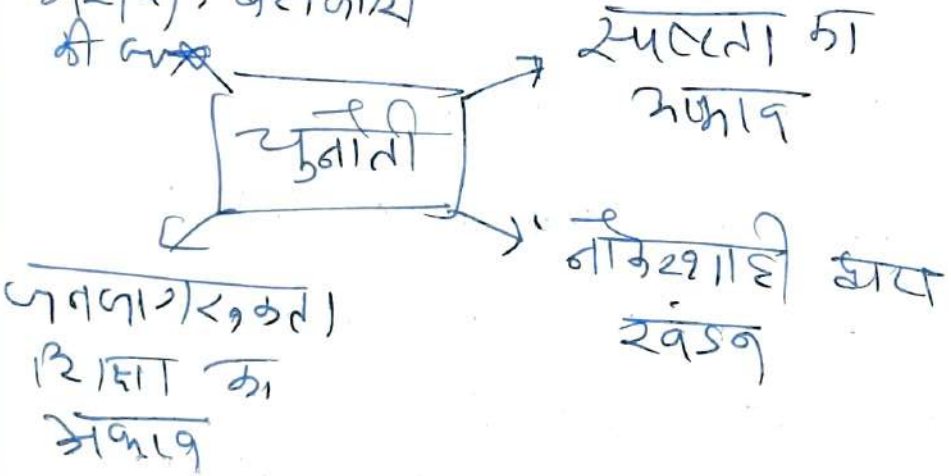

सामाजिक प्रभाव आकलन का उचित रूप से क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय की संकल्पना को साकार किया जा सकता है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तथा सामाजिक प्रभाव आकलन पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तथा मानव संसाधन विकास के लिए अनिवार्य है।

Only for arunrai.bha...

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the changes that have been witnessed in the caste system over the past few decades.
पिछले कुछ दशकों में जाति व्यवस्था में देखे गए परिवर्तनों को उजागर कीजिए।

उत्तर⇒ जाति भारतीय उपमहाद्वीप की अनूठी 'सामाजिक पदानुक्रमिक व्यवस्था' आधारित संस्था है। यह उत्तर वैदिक काल पश्चात् प्रचलन में आई परन्तु यह कुछ परिवर्तनों के साथ अद्यतन विद्यमान है।

जाति व्यवस्था

पारम्परिक रूप में	परिवर्तन वादी कारक	वर्तमान रूप में
• शुद्धता एवं पवित्रता पर आधारित • शुद्धता एवं प्रदुषण • श्रम विभाजन • उर्ध्वाधर रूप में विद्यमान	औद्योगीकिकरण शहरीकरण भूमण्डलीकरण आधुनिक शिक्षा राज्य की भूमिका (अनु.17 एवं अन्य)	• जाति: राजनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली • जाति, क्षैतिज रूप में अधिक प्रबल • योग्यतातंत्र तथा व्यक्तिवादी पर आधारित • तथाकथित उच्च जाति में केवल संस्कार तक सीमित

पिछले कुछ वर्षों में जाति व्यवस्था में देखे गए परिवर्तन

(क) राजनीतिक शक्ति के रूप में → 'जाति का राजनीतिकरण' तथा 'राजनीति का जातीयकरण' बढ़ा (रजनी कोठारी के अनुसार)

Only for anupramod...@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

→ लोकतंत्र में संख्या का महत्व: जाति एक समुदाय को लक्षित करती है > राजनीतिक आकांक्षा ↑
जैसे → BSP इत्यादि

→ (ख) नवीन संगठनों (सहचारी रूपों एवं पहचान) के रूप में

○ संगठन (सहचारी रूप)
- → जाति संघर्ष समिति (KR)
- → जाति पंचायत
- → बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP)
- → अखिल भारतीय जाति सभा

• नवीन पहचान
- → जातियाँ तथा उपजातियाँ
- → आरक्षण रहित तथा आरक्षित
- → दलित, महादलित इत्यादि।

(ग) श्रम विभाजन की जगह कर्म पर आधारित
- → कोई रोक टोक बिना नवीन अवसरों का लाभ उठना
- → दलित समुदाय का
  - → शिक्षक बनना
  - → सेना में जाना
  - → व्यापार करना
  - → कृषि करना

  ] सबकुछ संभव

जैसे: तमिलनाडु सरकार का पंडिताई हेतु टेस्ट लेना

(घ) 'संस्कृतिकरण' एवं 'प्रबल जाति' (श्रीनिवास के अनुसार) का प्रभुत्वशाली बनकर उभरना

(ङ) जाति का उर्ध्वाधर आधार की जगह क्षैतिज रूप में विस्तार

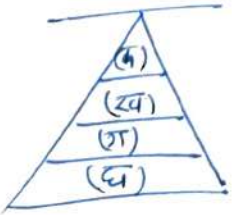

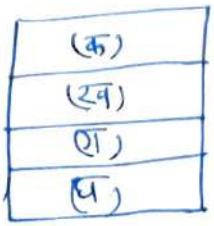

Only for arunrambha1270@gmail.com

VISION IAS™

(घ) सहभोज, अन्तरजातीय विवाह इत्यादि के कारण सम्मिलित संस्कृति एवं जाति का विकास

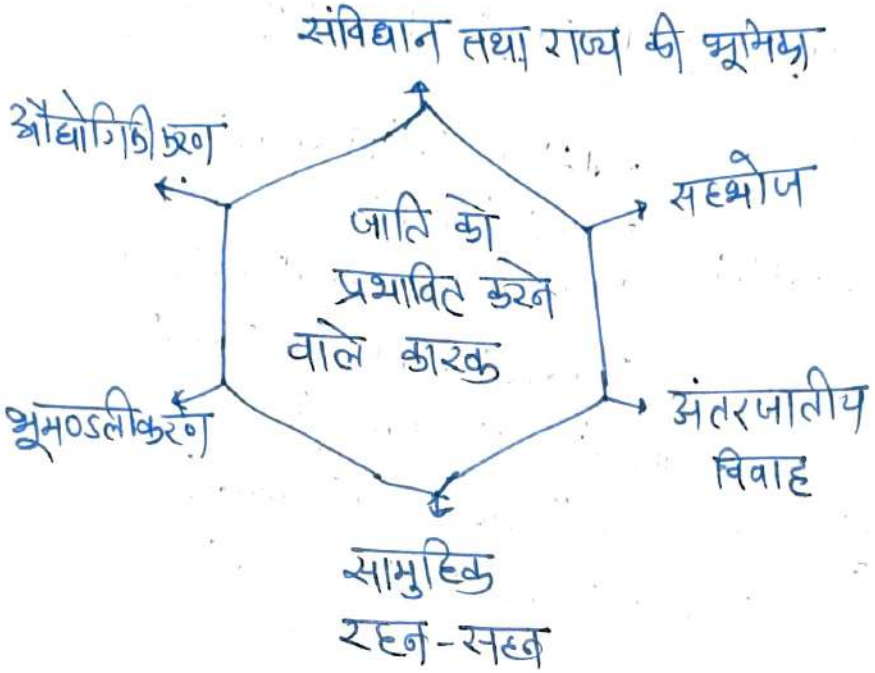

निःसन्देह जाति भारत में अद्यतन विद्यमान है परन्तु यह प्राचीन जड़ित संरचना से अभी 'लचीली संरचना' धारण कर रही है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Stating the problems arising due to haphazard urbanization in India, mention the steps taken by the government to address them.
भारत में बेतरतीब शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का उल्लेख करते हुए, सरकार द्वारा इनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर⇒ डेविस के अनुसार 'ग्रामीण जनता का शहरो में जाना और कार्य करना अर्थात् कृषि अर्थव्यवस्था से उद्योग अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति ही शहरीकरण कहलाती है।

शहरीकरण → शहरो द्वारा भौतिक सीमाओ (→ जनसंख्या, → क्षेत्रफल) में विस्तार ही शहरीकरण है।

शहरीकरण के कारण उत्पन्न समस्याएँ

(क) सामाजिक समस्याएं

• मलिन बस्तियो का निर्माण → स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव
↓
शरीर का बीमार होना
↓
अच्छी शिक्षा का अभाव
↓
कौशल विकास नहीं → रोजगार अवसर कम → गरीबी
↑
पोष्टिक आहार की कमी
↑
कुपोषण की समस्या

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything in the margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

७) शहरी कामगार महिलाओं की स्थिति खराब
- → आपराधिक कृत्यों में वृद्धि
- → स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्या
- → अकेलापन, अवसाद की समस्या
- → अत्यधिक / अतिरिक्त कार्य करने पर मजबूर

८) नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार
- → मुम्बई तथा बैंगलुरु जैसे शहरों में प्रवासी मजदूरों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार

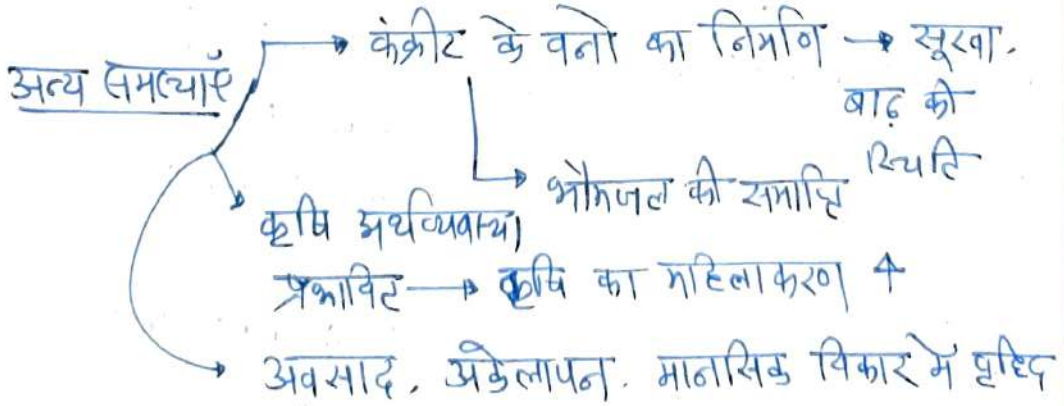

उपर्युक्त समस्याओं को देखकर सरकार इनसे निपटने के लिए विभिन्न उपाय भी कर रही है जैसे-

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(क) मजदूरों की श्रम संहिता में सुधार → न्यूनतम मजदूरी निर्धारित
↳ EPFO/ESIC द्वारा सामाजिक सुरक्षा

(ख) एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत मुफ्त राशन

(ग) मलिन बस्तियों की जगह → प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण

(घ) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना → समावेशी स्वास्थ्य परियोजना

* डाटा (Data) की प्राप्ति करना

(ङ) रेन गार्डनिंग, कियन गार्डनिंग तथा वाटर रेन हार्वेस्टिंग को बढ़ावा पर बल।

शहर आगामी भारत का भविष्य है अतः इससे उत्पन्न चुनौति को ध्यान में रखकर इसके सतत विकास पर बल देना चाहिए ताकि सामाजिक समावेशीकरण तथा SDG लक्ष्य - 11 (सतत शहरी विकास) प्राप्त किया जा सके।

6. Enumerate the salient features of Atmanirbhar Bharat Abhiyaan. Also, highlight the challenges that need to be overcome to make the initiative a success.

आत्मानिर्भर भारत अभियान की प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही, इस पहल को सफल बनाने के लिए उन चुनौतियों को रेखांकित कीजिए जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

उत्तर→ कोविड-19 के दौरान उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। अब यह जन आंदोलन बन गया है।

आत्मनिर्भर भारत: विशेषता

- स्वदेशी उत्पादन पर बल
- Local For Vocal पर नियम
- ग्रामीण संसाधनों का इस्तेमाल दोहन
- क्लस्टर युक्त योजनाओं का निर्माण
- विदेशी आय पर कम निर्भरता
- भारत का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्त बनना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आत्मनिर्भर भारत: चुनौतियाँ

- वित्त संबंधी चुनौतियां → आकड़ो को जोड़ तोड़ कर प्रकट किया गया।
- क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ
  - फंड
  - फंक्शन
  - फंक्शनरिज
  - → पंचायत
- संरक्षणवाद का आरोप
  - → विदेशी देशो द्वारा टैरिफ मे वृद्धि
- पूँजीपती वर्ग को अधिक लाभ (पूंजीवादी शासन प्रणाली)
- जनता के — जागरूकता, शिक्षा, सक्रियता — की कमी
- कोविड की अनसुलझी गुत्थी. अन्य जंगल - वायरस संबंधी बीमारियाँ

Only for ...@gmail.com

स्पष्टः आत्मनिर्भर भारत योजना सशक्त भारत का निर्माण करेगी इसी का परिणाम है कि भारत आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. What are the challenges faced by the transgender community in India? Enumerate the various steps taken to address these challenges.
भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन-सी हैं? इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर⇒

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 7० लाख ट्रांसजेंडर समुदाय (LGBTIQR) हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय से आशय जिनमें 'लिंग संबंधी विकृति' होती है से है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ

(1) स्वास्थ्य → पिंक मैगजीन के अनुसार भारत में लगभग 7०% समलैंगिक समुदाय HIV/AIDS से प्रभावित है।
- → कुपोषण की समस्या सर्वाधिक
- → एनीमिया तथा सिकलसेल रोग से ग्रसित
- → विशेषज्ञों का अभाव

(2) सामाजिक चुनौतियाँ
- → समाज द्वारा 'दोयम दर्जे' वाला समझना
- → सामाजिक बहिष्कार → परिवार द्वारा त्याग कर देना
- → सार्वजनिक स्थलों पर उनके लिए वाशरूम' की अलग से व्यवस्था नहीं
- → अपशब्दों का प्रयोग
- → सामाजिक न्याय तक पहुँच नहीं

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) आर्थिक चुनौतियाँ

- आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब
- काम के अवसर नहीं मिलता
- सरकारी - गैर सरकारी नौकरियो में आरक्षण नहीं
- भीख मांगने पर अथवा 'सेक्स वर्कर' के रूप में कार्य करने को मजबूर

(4) धार्मिक कार्यक्रमो में भी समलैंगिक लोगो को अशुभ की नज़र से देखा जाता है।

(5) भारतीय संसद में एक भी समलैंगिक प्रतिनिधित्व नही यहाँ तक सरकार के तीनो स्तरो में बहुत ही कम

- प्रशासनिक सेवाओ में नहीं
- अधिकांश में CEO/ कामगार के रूप में नहीं

समलैंगिको के साथ शुरु से अंतिम अवस्था तक विभिन्न प्रकार के भेदभाव किए जाते रहे है परन्तु सरकार एवं न्यायपालिका इस संदर्भ में संवेदनशील है तथा उसने कई कदम उठाए है -

(क) भारतीय दण्ड संहिता 'धारा-377' की समाप्ति

- समलैंगिको की आपस में शादी करना कानूनी रूप से मान्य
- भौतिक, मानसिक, शारिरीक संबंध बनाने का अधिकार 'महिला-पुरुषो' के समान ही।

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'ट्रांसजेंडरों' के लिए कार्य
- सतत विकास लक्ष्य-5 (लिंग समानता) ट्रांसजेंडर भी शामिल
- रंग-बिरंगे ध्वज का सभी जगह फहरना।

(ग) गैर-सरकारी संगठन → 'नाज फाउण्डेशन' समलैंगिकों मे होने वाली HIV/AIDS के प्रति जागरूकता फैलाता है। उन्हे 'प्रेवेन्टिव चेक्स' भी प्रदान करता है।

(घ) धार्मिक संगठन एवं साहित्य ग्रंथ → कुछ अपवादों को छोड़कर समलैंगिक समुदाय को धर्मों एवं साहित्यिक ग्रंथों में विशेष महत्व दिया गया है। जैसे - बच्चे होने पर इनका आशीर्वाद शुभ मानना।

- सिनेमा → दोस्ताना, मुम्बई मोडर्न लव ~~जैसे~~, सत्यमेव जयते संवेदनशीलता बढ़ाते है।
- साहित्य → समलैंगिक विमर्श पर विशेष अंक जैसें पिंक मैगजीन इत्यादि।

समलैंगिक समुदाय वर्तमान में हाशिए पर रखा है यह हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्हें मुख्य धारा में लाए ताकि हमारे संवैधानिक मूल्य 'सामाजिक न्याय' तथा SDG लक्ष्य-5 को प्राप्त किया जा सके।

Only for : nimrambha1270@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Right to information and transparency in administration are prerequisites for good governance. Elucidate.

सूचना का अधिकार और प्रशासन में पारदर्शिता सुशासन की पूर्वापेक्षाएं हैं। स्पष्ट कीजिए।

उत्तर ⇒

सुशासन से आशय सरकार एवं जनता के मध्य की दूरी को न्यूनतम कर लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा SMART (सहज, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी पारदर्शी) सरकार की स्थापना करने से है।

सूचना एक अधिकार और प्रशासन में पारदर्शिता से सुशासन निश्चित किया जा सकता है।

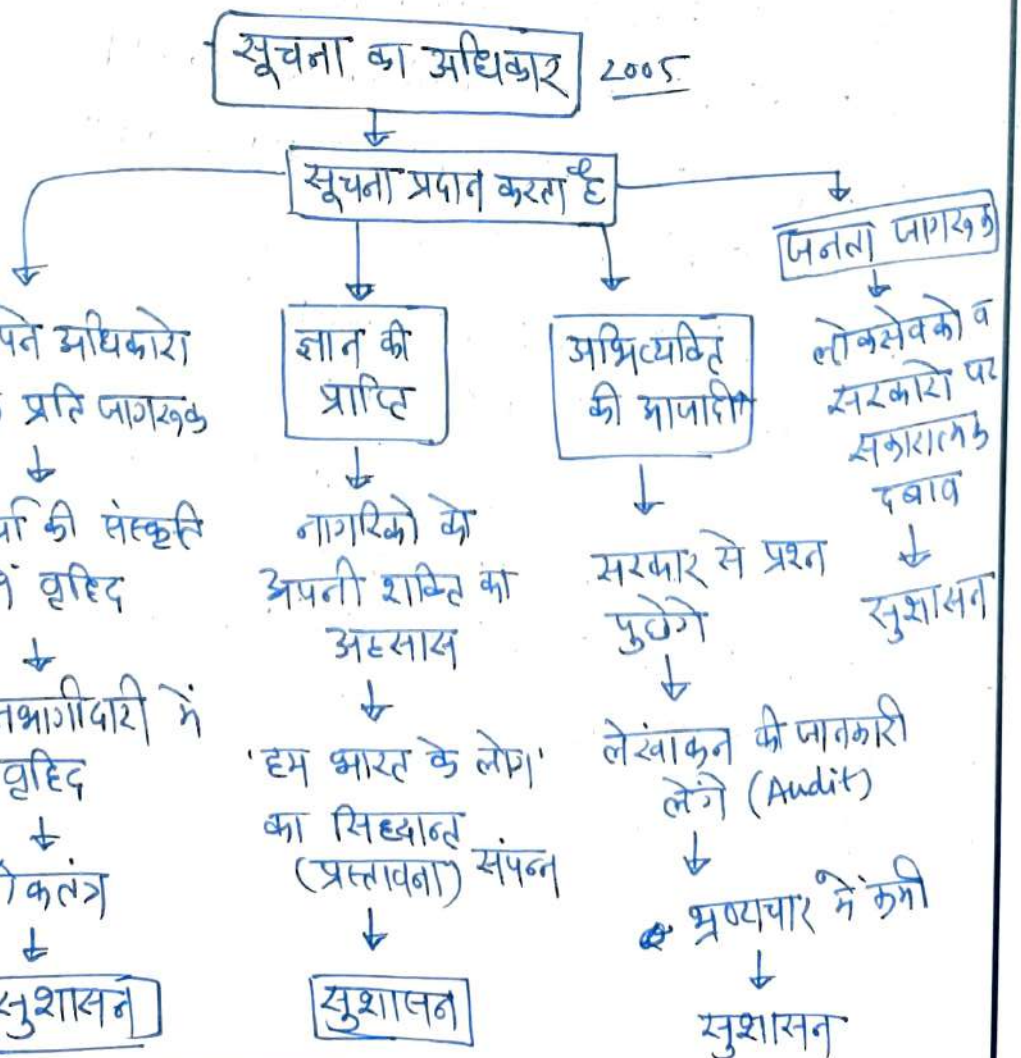

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

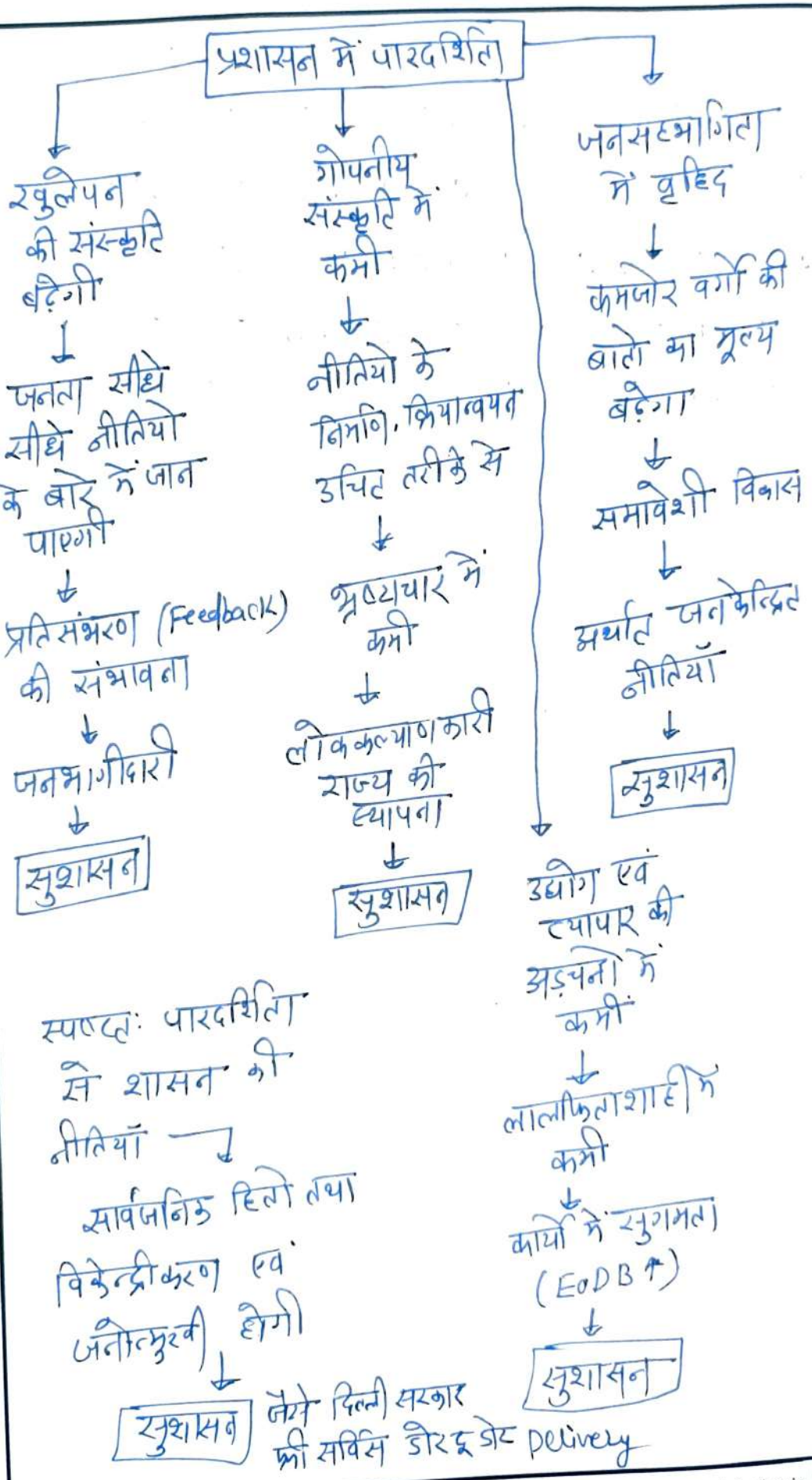

VISION IAS™

स्पष्टतः सूचना का अधिकार एवं पारदर्शी प्रशासन गोपनीयता के अंधकार से खुलेपन की संस्कृति की ओर, निरंकुशवादी शासन से जवाबदेही शासन तथा एकीकृत नीति निर्माण से जनभागीदारी की ओर ले जाएगा, जिससे सुशासन सुनिश्चित होगा।

Call us : 8468022022, 9019066066

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Analyse the significance and challenges associated with the adoption of e-governance in India.

भारत में ई-गवर्नेंस को अपनाने के महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर⇒

ई-गवर्नेंस से आशय शासन के सभी प्रतिमानों, सिद्धान्तों एवं मानदण्डों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से है।

ICT + Governance = E-Governance

ई-गवर्नेंस का महत्व

(i) सूचना (इन्फोरमेशन) → सूचना के त्वरित गमन हेतु आवश्यक

(ii) संवाद (कम्यूनिकेशन) → सरकार तथा विभिन्न अंगों के मध्य संवाद को सुचारु बनाने हेतु

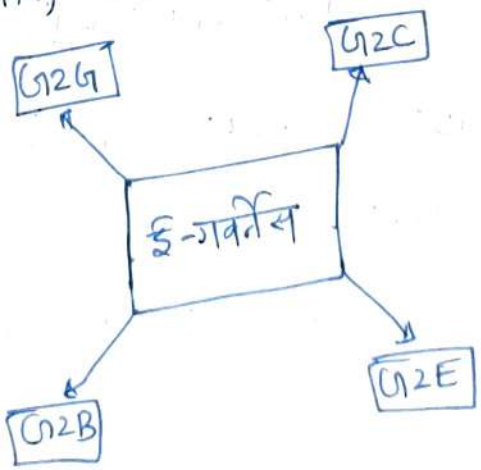

- G2G (सरकार से सरकार के मध्य) eg.→ खजाना (कर्नाटक)
- G2C (सरकार से नागरिक) जैसे → ज्ञानदूत (म.प्र.) लोकवाणी (उ.प्र.)
- G2B (सरकार से व्यापार) → MCA-21, E-taxation इत्यादि
- G2E (सरकार से कर्मचारी) → E-learning इत्यादि।

VISION IAS™

(iii) लेनदेन :- उद्योग एवं व्यापार तथा अन्य के मध्य त्वरित लेन देन प्रक्रिया हेतु आवश्यक

ई-गवर्नेंस अपनाने के अन्य महत्व

- पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बढ़ाना
- डाटा> वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित नीतियाँ
- सुशासन की स्थापना हेतु
- लोककल्याणकारी राज्य एवं समावेशी विकास हेतु
- इको फ्रेण्डली → निर्वनीकरण के बचाव
- उद्योग 4.0 संबंधी तकनीकियो से ढाँचागत परिवर्तन हेतु
- सुभेद्य वर्गो विशेषतः महिलाओ, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, समलैंगिक इत्यादि की सरकार तक पहुँच सुनिश्चित हेतु

परन्तु संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण इनके समक्ष चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई है जो सुशासन की स्थापना में बाधाएँ है जैसे -

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस आशा में कुछ ना लिखें)

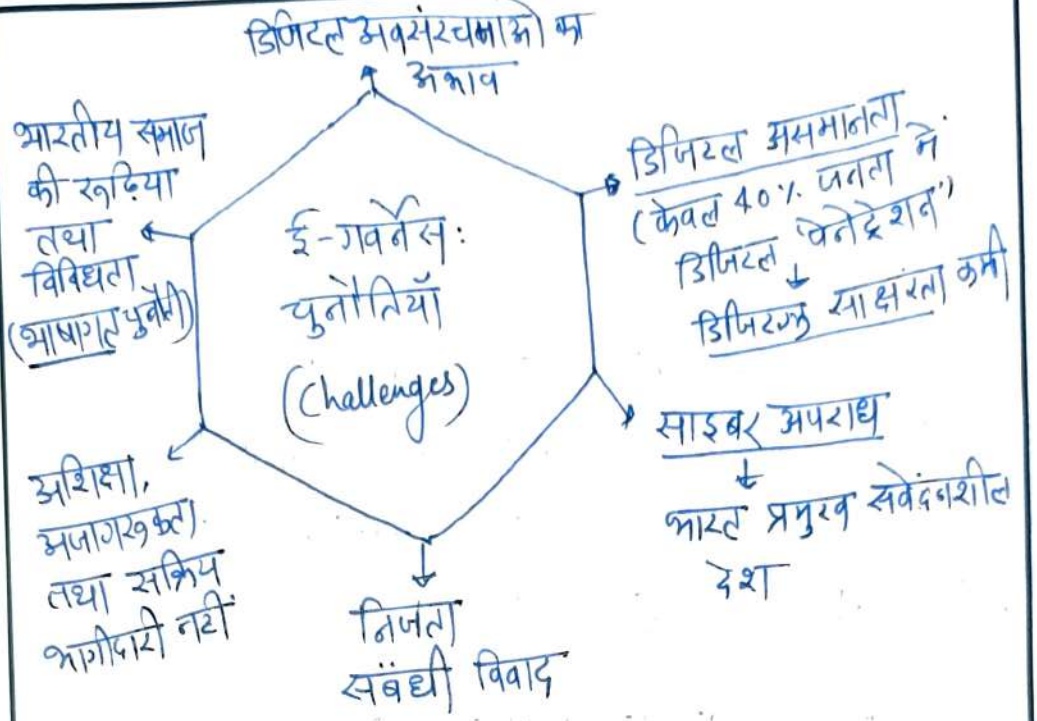

उपर्युक्त चुनौतियां एवं महत्व का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इसमे भारत की अपार संभावनाए निहित है। ई-गवर्नेंस केवल इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस नही है अपितु ईजी (Easy) गवर्नेंस इफेक्टिव (Effective) गवर्नेंस तथा इकानामिक (Economic) गवर्नेंस भी है। इसके कुछ 'की स्ट्रोक्स' देश मे करोड़ो लोगो के चेहरे पर खुशी ला सकते है।

सिंगापुर का 'सिंगापुर वन' माडल, दक्षिण कोरिया का मॉडल तथा राजस्थान सरकार का ई-गवर्नेंस संबंधी मॉडल उदाहरण है। IAS सुन्दरराजन (केरल कैडर) ने भी इस संदर्भ में विशेष प्रयास किए है।

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss how Citizen's Charter has emerged as an innovative tool for reinforcing citizen-centric governance. Also, list the various constraints faced in its effective implementation in India.

चर्चा कीजिए कि नागरिक-केंद्रित शासन को सुदृढ़ करने के लिए सिटीजन चार्टर किस प्रकार एक अभिनव साधन के रूप में उभरा है। साथ ही, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

सिटीजन चार्टर का आशय

नागरिको को प्रदान की जाने वाली सेवाओ के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नागरिक केन्द्रित शासन को सुदृढ़ करता है।

सिटीजन चार्टर → नागरिको को दी जाने वाली सेवाओ को नोटिस बोर्ड या अन्य माध्यम से लिखकर उनके समक्ष प्रस्तुत करना (2ARC)

नागरिक केन्द्रित शासन की स्थापना में सिटीजन चार्टर
- → पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता में वृद्धि → गोपनीय संस्कृति से खुली संस्कृति एवं जवाबदेह प्राधिकार की ओर
  ↓
  जनभागीदारी में वृद्धि
  ↓
  प्रतिसंभरण (Feedback) की व्यवस्था
  ↓
  जनता अनुरूप सेवाए नियम
  ↓
  जन केन्द्रित शासन
- → भ्रष्टाचार की संस्कृति में लगाम हेतु → जन केन्द्रित शासन
- → नागरिको तक सूचना की पहुँच आसान → जन केन्द्रित शासन
- → विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था → जन केन्द्रित शासन

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिटीजन चार्टर के समक्ष चुनौतियाँ

- 4A'Q
  - अवेलेबिलिटी (सुगमता)
  - अक्सेसेबिलिटी (सामर्थ्य)
  - अवेयरनेस (जागरूकता)
  - अफोर्डेबल (पहुँच नहीं)
  - क्वालिटी (गुणवत्ता)

  प्रमुख समस्या के रूप में (2ARC के अनुसार)

- भाषागत चुनौती → मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं
- विधिक प्रावधान नहीं → उल्लंघन की स्थिति में दंड / शास्ति का प्रावधान नहीं
  - संवैधानिक या विधिक (संविधिक) मान्यता नहीं
- केन्द्रीकृत अधिक → निर्माण प्रक्रिया में कुछ लोगों द्वारा निर्मिति → जनता की भागीदारी न के बराबर
- अनिवार्य प्रावधान नहीं तथा 'अपडेशन' नहीं → ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों सहित राज्य सरकार एवं मंत्रालयों में सिटीजन चार्टर कभी-कभी दिखता नहीं या अद्यतित (update) नहीं होता
- ऐसी जगह पर लगाना जहाँ आसानी से नजर न जाए जैसे → किसी कोने में लगाना इत्यादि

Only for arunrambha1270@gmail.com

VISION IAS™

'सिटीजन चार्टर' जनभागीदारी तथा नागरिक केन्द्रित शासन की स्थापना हेतु आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अनेक देशो ने इसे अपने यहाँ सशक्त प्राधिकार प्रदान किए है। भारत में इसे ओर अधिक चुस्त करने की आवश्यकता है।

Call us : 8468022022, 9019066066

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Although bureaucracy may seem to be at odds with democracy, it is much needed for the effective functioning of a democracy. Discuss in the context of India.

यद्यपि नौकरशाही लोकतंत्र के विपरीत प्रतीत हो सकती है, तथापि लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

उत्तर⇒

नौकरशाही सरकार और नागरिक के मध्य सेतु का कार्य करती है तथा नीतियो का निर्माण एवं क्रियान्वयन में भूमिका निभाती है।

नौकरशाही लोकतंत्र के लिए विपरित

- यदि औपनिवेशिक, बाबू मानसिकता न छोड़े
- अत्यधिक केन्द्रीकृत हो
- पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता का अभाव
- नैतिक मूल्यो की कमी
- वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता न हो
- अधिनायकवादी प्रवृत्ति अथवा code of conduct के अनुरूप न चलती हो।

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नौकरशाही प्रभावी लोकतंत्र के लिए आवश्यक

→ चुनाव प्रक्रिया → चुनाव प्रक्रिया मे नौकरशाही प्रबल रूप से कार्य करती है तथा चुनाव सम्पन्न कराती है।

(2) नीति क्रियान्वयन → नीतियो के क्रियान्वयन सबकी जिम्मेदारी प्रशासनिको के हाथो रहती है यहाँ तक की नीति निर्माण मे भी महत्वपूर्ण रहती है।

(3) जनता व सरकार के बीच सेतु का कार्य करती है।

(4) जनता के लिए कार्य करती है तथा संविधान के प्रति प्रतिबद्ध रहती है।

(5) सक्रिय राजनीति से तटस्थ रहती है।

(6) संविधान के अनुरूप कार्य करती

Only for arunrambha1270@gmail.com

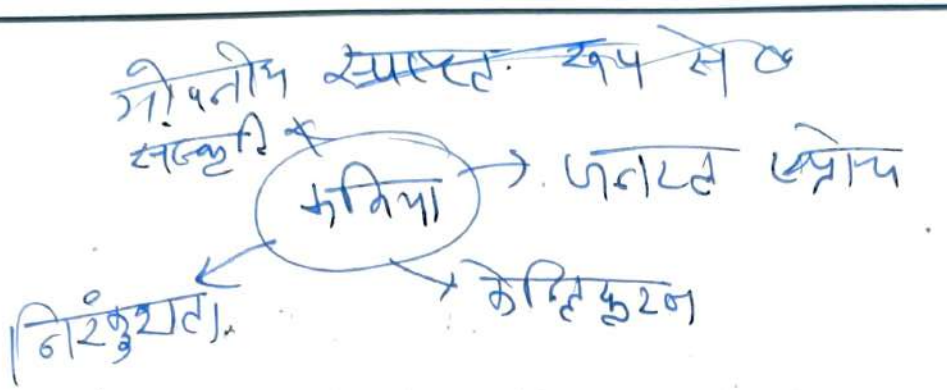

स्पष्टतः उपर्युक्त कमियों को दूर कर नौकरशाही को लोकतंत्र के वाइब्रेंट बनाया जा सकता है। 'मिशन कर्मयोगी' सफल प्रयास है

12. The potential of digital education cannot be fully realised unless the challenges of digital divide are overcome. Discuss.

जब तक डिजिटल डिवाइड से संबंधित चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता है, तब तक डिजिटल शिक्षा की संभाव्यता को पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सकता है। चर्चा कीजिए।

उत्तर ⇒

'डिजिटल डिवाइड' से आशय :

जनता के बीच 'डिजिटल पेनेट्रेशन' की उपलब्धता तथा कमी के मध्य की स्थिति से है। इसके बढ़ने से डिजिटल समावेशन प्रतिकूलतः प्रभावित होता है।

डिजिटल डिवाइड संबंधी चुनौतियाँ →
- डिजिटल अवसंरचनाओं का अभाव (भारत में केवल 40% जनसंख्या इन्टरनेट का इस्तेमाल करती है।)
- डिजिटल साक्षरता की कमी ग्रामीण क्षेत्र में 37% तथा शहरी क्षेत्र मे 61% लोग मोबाइल जैसे उपकरणों का डिजिटल अयोग कर सकते हैं।
- नेटवर्क, स्पेक्ट्रम तक पहुँच नहीं

उपाय →
डिजिटल शिक्षा का अत्यधिक उपयोग कर
↓
डिजिटल साक्षरता में वृद्धि
↓
डिजिटल अवसंरचनाओं की प्राप्ति
↓
डिजिटल पेनेट्रेशन में वृद्धि

डिजिटल शिक्षा हेतु सरकारी प्रयास

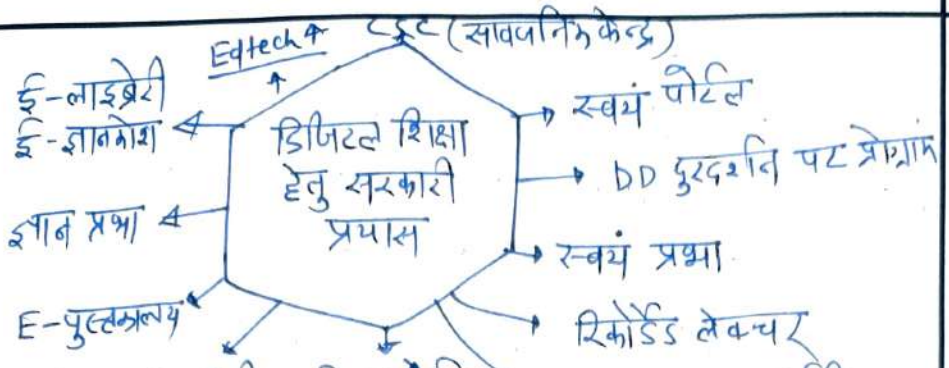

- Edtech
- टेट (सार्वजनिक केन्द्र)
- स्वयं पोर्टल
- DD दूरदर्शन पर प्रोग्राम
- स्वयं प्रभा
- रिकॉर्डेड लेक्चर
- डिजिटल युनिवर्सिटी
- दिक्षा प्रोटल
- नेशनल लाइब्रेरी
- E-पुस्तकालय
- ज्ञान प्रभा
- ई-लाइब्रेरी
- ई-ज्ञानकोश

सरकार के अन्य प्रयास

→ PMG-DISHA → प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
↓
हालिया रिपोर्ट 5 करोड़+ ग्रामीण महिलाओं को डिजिटली साक्षर किया

→ भारतनेट प्रोजेक्ट → ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच हेतु प्रकाशिक तंतु (OF) की अवसंरचना → कनेक्टिविटी में वृद्धि

→ 5जी स्पेक्ट्रम → चौथी पिढ़ी के पश्चात सरकार पाँचवी पीढ़ी को इन्टरनेट का सम्पूर्ण भारत में प्रसार
↳ डिजिटल कार्यों में तीव्रता

→ उद्योग 4.0 के प्रति रुचि → तकनीकी उद्योग 4.0 के प्रति सरकार ने सकारात्मक रुख रखा है

→ डाटा सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा हेतु
↳ 'डाटा लोकेलाइजेशन' पर बल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Only for arunrambha1270@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

कोविड़-19 के पश्चात डिजिटल शिक्षा अधिक प्रासंगिक हो गयी है। सरकार उपर्युक्त उपायों से डिजिटल समावेशन में वृद्धि कर सतत विकास लक्ष्य - 4 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगी। PM श्री स्कूल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Provide an account of the role played by NGOs in rural development in India, with examples.

उदाहरण के साथ भारत में ग्रामीण विकास में गैर सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण प्रदान कीजिए।

उत्तर ⇒ गैर सरकारी संगठन ऐसे संगठन है जो सरकार से इतर रहकर समाज की आवश्यकताओं तथा समस्याओं को समझकर निः स्वार्थ भाव से इन्हें न्यून करने का प्रयास करते है। यह 'ग्रामीण विकास' का भी कायाकल्प कर रहे है।

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठन की भूमिका

(क) ग्रामीण औद्योगीकीकरण ⇒ ~~गैर~~ NGOs ग्रामीण क्षेत्रो में 'संसाधन आधारित क्षेत्रों की पहचान कर ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योग में बढ़ावा दे रहे हो

जैसे:- ग्रामोदयोग नामक, गैर-सरकारी संगठन मालवा क्षेत्र (म०प्र०) मे ग्रामीण औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ा रहा है।

(ख) ग्रामीण जनभागीदारी ⇒ 'सेवक' (उत्तराखण्ड) जैसे संगठन ग्रामीण लोगो की ~~नीति निर्मा~~ आवश्यकतानुरूप नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन तथा नीति मूल्यांकन में सरकार एवं ग्रामीणों के मध्य सेतु का कार्य करता है।

Don't write anything in margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) असंगठित कामगारो का विकास → ग्रामीण क्षेत्रो के असंगठित पुरुषो एवं महिलाओ को 'सामाजिक सुरक्षा' तथा कार्य मुहैया करवाना। उदाहरण → सेवा (SEWA) एवं स्वयं गैर सरकारी संगठन।

(घ) शिक्षा जागरुकता → सकल नामांकन अनुपात (GER) बढाने हेतु तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उचित MDM (मध्याह्न भोजन) की प्राप्ति हेतु कार्य
उदाहरण → सुलभ शिक्षा (बुन्देलखण्ड) जैसे NGOs

(ङ) डिजिटल समावेशन → 'डिजिटल अर्थव्यवस्था' में भागीदारी बनने हेतु
→ सामानो की आनलॉइन बिक्री हेतु
→ इण्टरनेट की पहुंच सुलभता हेतु
जैसे → ग्रामटेक गैर सरकारी संगठन एवं अन्य

(च) कृषि के विकास हेतु → आधुनिक कृषि हेतु
→ सुक्ष्म लोन तथा अन्य ऋण प्राप्ति हेतु
→ फसल विविधीकरण एवं मृदा संरक्षण हेतु
→ सुक्ष्मयंत्रो से सिंचाई तथा सतत कृषि हेतु
कई NGOs कार्य कर रहे।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

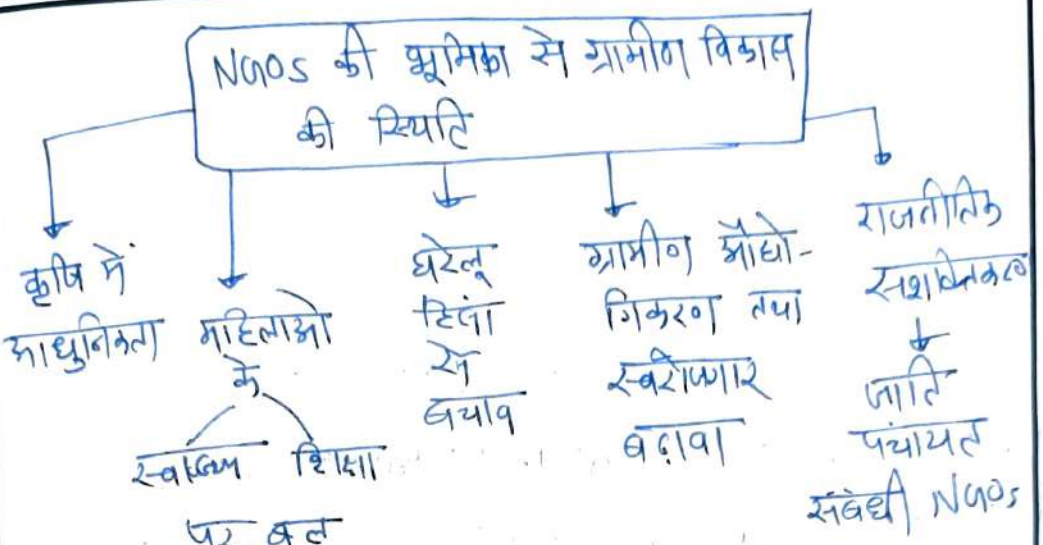

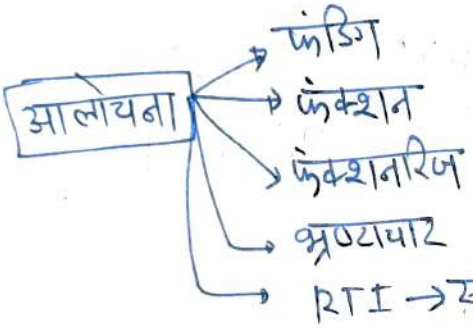

स्पष्टतः गैर सरकारी संगठन ग्रामीण विकास में सहायक है परन्तु इनके साथ ही अन्य नागरिक संगठनों, प्रशासनिक मशीनरी तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का भी विशेष महत्व है।

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(8)

14. India has a unique opportunity to develop before population ageing sets in. In this context, analyse how India can reap its demographic dividend going forward.

जनसंख्या में वृद्ध लोगों की अधिक हिस्सेदारी आरंभ होने से पहले भारत के पास विकसित होने का एक अद्वितीय अवसर है। इस संदर्भ में, विश्लेषण कीजिए कि भारत आगे बढ़ते हुए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है।

उत्तर ⇒

'जनसांख्यिकीय लाभांश' उस स्थिति को कहते हैं जब ~~किसी निश्चित~~ कार्यशील आयु (15-59 वर्ष) का अनुपात अकार्यशील/निर्भर जनसंख्या की तुलना में अधिक हो। भारत अभी 'जनसांख्यिकीय लाभांश' की स्थिति में है।

जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति के लाभ

→ (अ) श्रम बल में वृद्धि

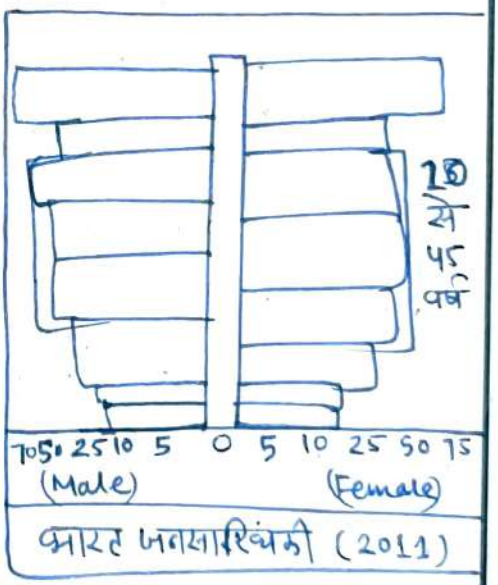

↓

कार्यक्षमता एवं कार्यगुणवत्ता में वृद्धि

↓

कृषि | उद्योग | सेवा

↓

उत्पादकता वृद्धि → अधिशेष

↓

व्यापार लाभ

↓

GDP में वृद्धि

भारत जनसांख्यिकी (2011)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ब) संसाधनो का इष्टतम दोहन → जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में 'सतत विकास' को ध्यान में रखकर

↓

संसाधनो का अधिकतम दोहन

↓

संसाधनो से लाभ प्राप्ति

- ↓ आर्थिक संवृद्धि
- ↓ सामाजिक संवृद्धि
- ↓ मानसिक संवृद्धि

(स) प्रसंस्करण में वृद्धि

- → खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण
- → उद्योगों में मूल्य उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन कर

↓

मूल्य प्राप्ति में वृद्धि

(द) सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति

- → स्वास्थ्य
- → शिक्षा
- → विमर्शी समुदायों से संबंधित विमर्शों पर बल

अत्यधिक जागरूकता

↓

अत्यधिक लाभ

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जनसांख्यिकी लाभ कैसे प्राप्त हो

→ कौशल विकास ↑
→ संसाधनों का इष्टतम दोहन
→ स्वास्थ्य, भूख संबंधी मूलभूत समस्याओं के उन्मूलन से
→ शिक्षा (गुणवत्तापूर्ण) तथा व्यवसायिक शिक्षा में वृद्धि

स्पष्टतः जापान जैसी स्थिति न बने उससे पूर्व भारत को अपनी जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना होगा। नई शिक्षा नीति तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र महत्वपूर्ण साबित हो सकते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Despite various measures, why does manual scavenging continue to persist in India?

विभिन्न उपायों के बावजूद, भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा क्यों जारी है?

उत्तर ⇒ भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 मे हाथ से मैला ढोने की प्रथा को विधिक रूप से समाप्त कर दिया परन्तु यह प्रथा अद्यतन विद्यमान है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा
→ जाति का पदानुक्रमिक संरचना मे निचले पायदान वाले लोगो द्वारा मैला उठाना
→ मैला को हाथ से उठाना तथा उसे सर पर ढोकर ले जाना।

भारत में मैला ढोने की प्रथा के रहने के कारण

→ (क) जाति व्यवस्था → भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जाति विशेष के व्यक्ति को (तथाकथित दलित) यह सुनिश्चित करती है कि वह अपने हाथ से मैला उठाएं।
→ सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं द्वारा स्वीकृति प्राप्त प्रथा।

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ख) रोजगार → तथाकथित निम्न जाति के लोगो के रोजगार का अभाव होने के कारण यह कार्य मजबुरी में करना पडता है।

(ग) नवीनतम तकनीकियो का अभाव → भारत में आज स्वच्छ भारत अभियान तथा WASH योजना के तहत सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। परन्तु रोबोट्स, कृत्रिम मेधा, स्वचालित मशीन इत्यादि के अभाव में लोगो को अपने हाथो से मैला उठाना होता है।

(घ) वित्तीय अभाव → वित्त संबंधी चुनौती भी अत्यधिक महंगी मशीनो पर खर्च नही करना चाहती।

(ङ) राजनीतिक एवं प्रशासनिक शिथिलता
↳ राजनीतिक दृढ़ता के अभाव में कठोरतम नीति तथा प्रशासनिक दक्षता के अभाव में क्रियान्वयन संबंधी लिकेज द्वारा यह अप्रभावी बना हुआ है।

(च) सफाई टैंको, नालियो, चोक इत्यादि की जटिल सफाई मानवो के द्वारा ही संभव होती है।

Only for arunrambhai270@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

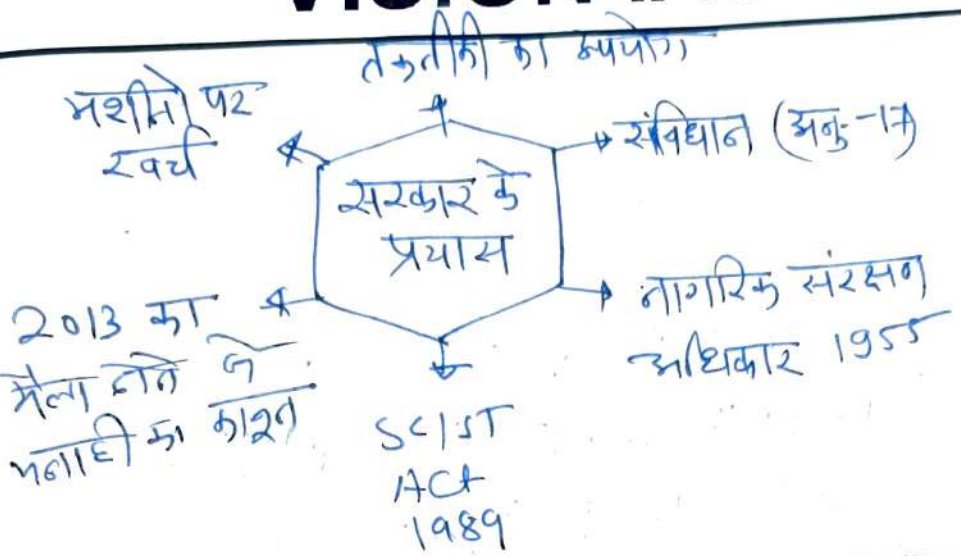

पिछले पांच वर्षों में सेप्टिक टैंक में करीब 500+ लोगों की मृत्यु हुई। अतः इस गंभीर स्थिति से बचने हेतु तकनीकी का इस्तेमाल रोबोट, मशीन लर्निंग करना होगा ताकि मानवाधिकारों की रक्षा कर सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके

Visit us : www.visionias.in

8019066066

Don't write anything in margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Highlight the significance of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and discuss the issues associated with it.

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के महत्व पर प्रकाश डालिए और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर⇒ देश में बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियाँ विशेषतः महिला एवं बच्चों संबंधी रोगों के कारण स्वास्थ्य संरचना जर्जर होने लगी। इसी स्थिति को सुधारने हेतु 2017 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गयी

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY का महत्व

- → समावेशी स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु
- → Health Insurance (स्वास्थ्य बीमा) प्रदान हेतु
- → महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रोगों > निवारण
- → 5 लाख तक का कवरेज
- → UN 'युनिवर्सल हेल्थ कवरेज' को सफल करने हेतु
- → आयुष्मान भारत मिशन शुरू
- → सतत विकास लक्ष्य-3 'अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन' की प्राप्ति हेतु।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अन्य महत्व
- → मरीज का जेब खर्च कम करने हेतु
- → स्वास्थ्य में GDP का खर्च 1.6 से बढ़ाकर 2.5% तक करने हेतु
- → प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना एवं उच्च स्वास्थ्य संगठन में सुधार

जन आरोग्य योजना से संबंधित मुद्दे

- **पात्रता** → कई गरीब एवं भिखारी तथा अन्य सुभेद्य वर्गों तक पहुँच नहीं
- **संघवाद** → केन्द्र राज्य संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव
  - पश्चिम बंगाल, राजस्थान द्वारा नहीं अपनाना
- **वित्त** → वित्त बढ़ाने का दावा परन्तु मैकेनिज़्म की व्याख्या नहीं जिससे इसे बढ़ाया जाए।
- पर्याप्त जानकारी नहीं → किन-किन चिकित्सालयों में इससे संबंधित सुविधाएँ मिलेगी यह स्पष्ट नहीं
- क्रियान्वयन संबंधी चुनौती
  - → भ्रष्टाचार
  - → नौकरशाही उदासीनता
  - → मरीजों का दुर्व्यवहार

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सतत विकास लक्ष्य 3 तथा सब तक स्वास्थ्य (Health for All) की अवधारणा हेतु यह एक महत्वपूर्ण योजना है अतः इसकी असंगति को जानकर उचित क्रियान्वयन पर बल देना होगा।

17. National e-Governance Plan in Agriculture (NeGPA) is a positive move towards digitizing agriculture in India. Discuss.

कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA) भारत में कृषि के डिजिटलीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। चर्चा कीजिए।

उत्तर⇒ कृषि भारत की लगभग 60% से अधिक जनसंख्या को प्रत्यक्षतः एवं परोक्षतः रोजगार प्रदान कराता है परन्तु पारम्परिक कृषि कार्यों से लाभ की संभावना कम बनी रहती है इसलिए NeGPA शुरू किया

NeGPA की प्रमुख विशेषता

- कृषक तथा सरकार के बीच के अंतराल को कम करना
- कृषकों तक सुशासन की पहुँच सुनिश्चित
- कृषि भूमि का डिजिटल रिकार्ड रखना जैसे e-भूमि प्रोजेक्ट (KR)
- कृषकों हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान करना
- उत्तम गुणवत्ता के बीज, सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, फव्वारा इत्यादि देना
- उर्वरकों की गुणवत्ता में वृद्धि जैसे नीम लेपित यूरिया, तरल यूरिया, नैनो पिंक नैनो DAP इत्यादि देना
- विपणन कार्यों में सुगमता E-NAM जैसे पोर्टल

Only for arunrambha1270@gmail.com

NeGPA से कृषि का डिजिटलीकरण

- कृषि भूमि संबंधी समस्त रिकार्डों को अभिलेखों के रूप में डिजिटली संरक्षित रखना
- कृषक लोन संबंधी कार्यों में सुगमता
  - आधार, मोबाइल नंबर तथा खाता नंबर का लिंक करना
- विपणन के समय → सभी मंडियों के भाव एक प्लेटफार्म पर दिखाना
  - देश के किसी भी भाग में अपने उत्पाद को बेचना (ENAM)
- सिंचाई संयंत्रों (सोलर पैनल युक्त) का नियंत्रण अपने डिजिटल संयंत्र की सहायता से
- भावान्तर जैसी म.प्र. सरकार की योजना जिसमें कृषकों की निश्चित फसल (MSP दाइप) मोबाइल फोन मैसेज, email के माध्यम से खरीदी जाती है।
- बिचौलिया संस्कृति का उन्मूलन

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्पष्ट: NeGPA से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा तथा ICAR, IARI. के अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशासनिक एवं राज्य की लोककल्याणी नीतियों से इसका कायाकल्प संभव है।

Visit us : www.visionias.in

Call us : 8468022022, 9019066066

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. What do you understand by minimum government and maximum governance? State the initiatives taken by the government in this regard in recent times.

न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन से आप क्या समझते हैं? हाल के दिनों में इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर⇒

सुशासन की स्थापना हेतु तथा सरकारी मिशनरी का बढ़ता प्रभाव कम करने हेतु न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन की शुरुआत की गई।

न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के निहितार्थ

- सरकारी मिशनरियो के बढ़ते प्रभाव को कम करने हेतु
- बाजार व्यवस्था को मुक्त बनाने हेतु ताकि कार्यों में सुगमता (EODB) रहे
- नागरिक केन्द्रित नीतियो के निर्माण हेतु
- बिचौलिया संस्कृति की समाप्ति हेतु
- जनभागीदारी में वृद्दि करने के लिए
- आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास की प्राप्ति हेतु
- नागरिकोन्मुखी सरकार निर्माण हेतु

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- लोकतंत्र तथा संविधान में व्याप्त लोक-कल्याणकारी राज्य (अनु. 38) तथा 'जनता के लिए' कार्य सेवा भावना से
- देश के उद्योगो सेवा क्षेत्रो में नवीनतम अवसरो की शुरुआत हेतु
- डिजिटल कम्पनियो तथा स्टार्टअप को बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने के लिए
- अनुसंधान एवं विकास हेतु

सरकार द्वारा की गई हालिया पहले

- प्रशासनिक मशीनरी में सुधार
  - मिशन कर्मयोगी
  - 'Rule Based to Role Based'
  - File to Field' प्रशासन
- लाइसेंसिंग व्यवस्था में कमी करना अथवा उन्हे समाप्त करना
- विदेशी निवेशको में वृद्धि हेतु कई क्षेत्रो में 100% FDI सुधार
- नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनो, स्वयं सहायता समूहो तथा अंतराष्ट्रीय संगठनो की भागीदारी वाली
- जनकेन्द्रित शासन

Only for arunrambha1270@gmail.com

2069
VISION IAS™

निष्कर्ष: न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन की पहल अनूठी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की अवधारणा को ध्यान रखकर इसे सुचारु करना चाहिए।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : ...

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Give an account of the role played by women's organisations to improve the status of women in post-independent India.

स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण प्रस्तुत कीजिए।

उत्तर⇒ महिलाओ की स्थिति में सुधार करने हेतु समय समय पर अनेक आंदोलन हुए परन्तु आजादी पश्चात महिला सुधार आंदोलन की विशेषता थी कि महिलाएं स्वयं इनमे सक्रिय रूप से शामिल थी

महिला सुधार पर एक नज़र

→ भारतीय पुनर्जागरण काल मे सती प्रथा, विधवा विवाह, निषेध, बाल विवाह इत्यादि का विरोध

→ स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिला संगठन

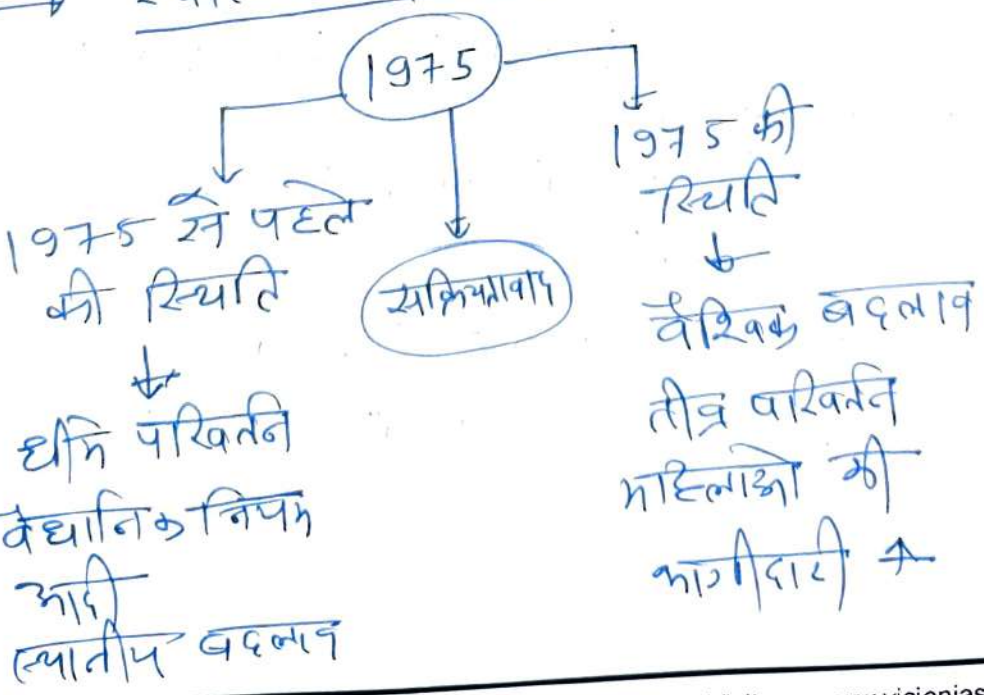

Only for arunrambha1270@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महिला संगठन की भूमिका

(I) सेवा (SEWA) → यह एक स्वयं सहायता समूह
↳ असंगठित कामगारों की महिलाओं हेतु प्रावधान
↓
रोजगार मुहैया, आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण

(II) आदिवासी महिला क्रांतिकारी संगठन
↳ आदिवासी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई
→ वनोपज से लाभ
→ जल-जंगल जमीन के लिए लड़ाई

(III) वनीता → यह गैर सरकारी संगठन है जो महिला पोषण संबंधी कार्यों को देखता है।
→ महिला स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति प्रतिबद्ध

(IV) महिला कामाख्या → यह संगठन भी महिलाओं विशेषतः ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रदान करता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(V) UN WOMEN → संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक संस्था है।
↳ महिला अधिकारों के लिए स्थापित

(VI) कुदुम्ब श्री (केरल) → SHGs
↳ कुटीर एवं लघु उद्योग में महिला भागीदारी बढ़ता है।

(VII) Metoo Campaign → सोशल मिडिया पर चला वैश्विक अभियान जो महिलाओं के सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति लड़ाई लड़ने पर बल देता है।

स्पष्टः भारत सहित विश्व में अनेक ऐसे संगठन है जो महिलाओं की स्थिति के सुधार हेतु लगातार प्रयास का रहे है। पितृसत्तात्मक सोच तथा मानसिक परिवर्तन का स्थिति बदल सकते है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. Highlight the measures taken by the government to promote Self Help Groups (SHGs) in India. Also, discuss the issues that SHGs continue to face.
भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिनका सामना SHGs कर रहे हैं।

उत्तर ⇒ स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक हितो वाले महिला / पुरुषो का स्वैच्छिक संगठन होते है। यह श्रमजीवी वर्ग से उद्यमी वर्ग का निर्माण करता है।

स्वयं सहायता समूह एवं सरकार के प्रयास

- महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 50% तक स्वयं सहायता समूह SHGs > आरक्षित
- ऋण प्राप्ति → NABARD के बैंकिंग लिंकेज प्रोग्राम SHGs के तहत सुक्ष्म वित्त की प्राप्ति आसान
- कर संबंधी छूट के प्रावधान
- ग्रामीण प्रशासनिक संस्था द्वारा विशेष कार्य करने पर बल
  - → देश में लगभग 6.9 मिलियन से अधिक SHGs हो गए है।
- वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना
- पंजीकरण

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- निवारण तंत्र, शिकायत निवारण तंत्र
- नोडल अधिकारी की नियुक्ति
- तृणमूल स्तर की सरकार अर्थात् स्थानीय स्वशासन से विशेष फंड की सुविधा

SHGs के समक्ष उत्पन्न मुद्दे

- वित्तीय अस्थिरता → पैसे की स्थिरता का अभाव
- जनजागरूकता तथा शिक्षा का अभाव
- फ्रॉड, स्कैम के बढ़ते प्रयत्न
- प्रशासनिक नौकरशाही का अत्यधिक दखल
- पुरुषवादी सोच का महिलाओं को कार्य पर न भेजना
- प्रसंस्करण हेतु तकनीकी का अभाव
- समान ब्राडिंग समस्याएँ
- समावेशी विकास नहीं

Only for arunrambha1270@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण तथा उद्यमी वर्ग के सृजन हेतु आवश्यक है अतः वित्त की सुनिश्चितता तथा अधिक अधिकार प्रदान कर इन्हे सक्रिय किया जा सकता है।

Only for anuradha1270@gmail.com